(ग) जी, नहीं। व्यापक फसल बीमा योजना के अंतर्गत मध्य प्रदेश प्रमुख लाभानुभोगियों में से एक है। योजना के क्रियान्वयन के लिए यूनिट क्षेत्र का फैसला उपज के आंकड़ों की उपलब्धता तथा प्रत्येक अधिसूचित क्षेत्र में निर्धारित न्यूनतम संख्या में फसल कटाई प्रयोग करने की क्षमता के अध्यधीन राज्य सरकार को करना होता है।

Sale of Free Sale Sugar

4272. SHRI SURESH PACHOURI: Will the Minister of FOOD be pleased to state:

(a) whether it is a fact that Government have put restrictions on the sale and despatch of free sale sugar by mills on weekly instead of fortnightly basis;

(b) if so, what were the reasons for taking such a decision and to what extent this decision will ensure that indigenous sugar is not held back by the mills;

(c) whether it is also a fact that to give a boost to sugar exports it has also been decided that public sector units like STC and MMTC would also undertake import of sugar udner OGL; and

(d) if so, to what extent these curbs imposed on free-sale sugar will help in reducing price of sugar and also in making sugar available freely?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF FOOD (SHRI KALP NATH RAI): (a) Yes, Sir.

(b) Weekly restrictions have been imposed to ensure uniform flow/ availability of sugar in the market at a reasonable price. Sugar factories are rquired to comply with this stipulation and any default in this regard would amount to contravention of the statutory orders.

(c) Sugar is beign imported by STC/ MMTC under OGL to meet the requirements of sugar for the Public Distribution System in the country.

(d) The various measures taken by Government, including weekly restrictions on sale and despatch of free sale sugar, have helped to augment availability of sugar and to reduce its price in the open market. The wholesale prices of S-30 grade of sugar in the four prinicipal markets of the country which were in the range of Rs. 1483 to Rs. 1630 per quintal on 19th May, 1994 have declined to the range of Rs. 1268 to Rs. 1385 per quintal as on 18-8-1994.

मध्य प्रदेश को खाद्यानों की आपूर्ति

4273. **श्री दिलीप सिंह जूदेव:** क्या खाद्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या मध्य प्रदेश सरकार ने केन्द्रीय सरकार से वर्ष 1994-95 के दौरान राज्य में जिलों में खाद्यानों की आपूर्ति किए जाने के लिए केन्द्रीय पूल से अतिरिक्त मात्रा खाद्यान प्रदान करने की मांग की है;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है;

(ग) उपर्युक्त वर्ष के दौरान राज्य की जिला-वार वास्तविक मांग कितनी है; और

(घ) इस संबंध में सरकार द्वारा लिए गए निर्णयों का ब्यौरा क्या है?

खाद्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कल्प नाथ राय): (क) और (ख) मध्य प्रदेश सरकार से 38, 657 मीटरी टन खाद्यानों का अतिरिक्त आवंटन करने विषयक एक अनुरोध प्राप्त हुआ था। सम्पुष्ट सार्वजनिक वितरण प्रणाली की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए जुलाई, 1994 से मध्य प्रदेश को चावल और गेहूं, प्रत्येक का 7660 मीटरी टन प्रति मास अतिरिक्त आवंटन करने की इजाजत दी गई है।

(ग) और (घ) सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लिए मध्य प्रदेश सहित विभिन्न राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को केन्द्रीय पूल से खाद्यानों का आवंटन और अतिरिक्त आवंटन केन्द्रीय पूल में स्टाक की स्थिति, विभिन्न राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों की सापेक्ष आवश्यकताओं, उठान की प्रवृत्ति, मौसमी उपलब्धता और अन्य संगत तथ्यों को ध्यान में रखकर प्रत्येक मास के आधार पर किया जाता है। ये आवंटन समूचे राज्य के लिए होते हैं और अनिवार्य रूप से अनुपूरकस्वरूप के होते हैं और इनसे राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों की समूची मांग को पूरा करने की उम्मीद नहीं की जाती है। राज्य के अन्दर उनके वितरण, जिसमें उनके क्षेत्र तथा उपभोक्ताओं को दी जाने वाली मात्रा शामिल है, के बारे में राज्य सरकार द्वारा निर्णय और प्रबन्ध किया जाता है।

Distribution of Substandard Commodities by FCI

4274. SHRI KANAKSINH MOHANSINH MANGROLA: Will the Minister of FOOD be pleased to state:

(a) whether substandard wheat, sugar, rice, palmolein etc. are distributed by the Food Corporation of India to the customers through Fair Price Shops in Gujarat;

(b) whether it is also a fact that sugar is not available at the ration shops now-a- days;

(c) if so, the details thereof; and

(d) what action Government have taken or propose to take in this regard?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF FOOD (SHRI KALP NATH RAI): (a) to (d). WHEAT AND RICE: Wheat and Rice supplied by Food Corporation of India from its godowns/depots to the State Governments and their nominees for Public Distribution System (PDS) conform to the P.F.A. specifications. The stocks are issued after that State Governments' nominees satisfy themselves both about the quality and quantity. No complaint has been received from Government of Gujarat regarding sub-standard foodgrains supplied by FCI for PDS in Gujarat.

PALMOLEIN: Palmolein is supplied by the State Trading Corporation of India to the State Governments including Gujarat against allocations made by Government of India for P.D.S. and no complaint about the quality thereof has been received either from the State Government or from any other quarter.

SUGAR: Food Corporation of India is not handling levy sugar in the State of Gujarat. It is the responsibility of the State Governments/ Union Territories to arrange for actual distribution of commodities lifted from F.C.I. and other Central Agencies to the Fair Price Shops and to supervise the distribution to consumers.

Surplus Foodgrains

4275. SHRI BHUPINDER SINGH MANN: Will the Minister of FOOD be pleased to state:

(a) whether Government's attention has been drawn to the news-item "Foodgrain surplus worries Centre" published in the "Tribune" of 9th August, 1994;

(b) if so, in view of the surplus foodgrains to the tune of 30.8 million tonnes, whether Government are still planning to dump more foodgrains by import; and

(c) whether Government will above remove restrictions on export of foodgrains?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF FOOD (SHRI KALP NATH RAI): (a) Yes, Sir. Government has seen the news item.

(b) No, Sir.

(c) The policy of exports of foodgrains is reviewed on a continuous basis. It is decided keeping in view the demand/ supply position of the foodgrains.

गेहूं के केन्द्रीय निर्गम मूल्य के सम्बन्ध में समिति

4276. **श्री राम जेठमलानी:** क्या खाद्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने गेहूं के केन्द्रीय निर्गम मूल्य को बढ़ाने के सम्बन्ध में विचार-विमर्श करने हेतु मंत्री-स्तर की एक पांच सदस्यीय समिति गठित की है;

(ख) यदि हां, तो यह समिति कब गठित की गई थी तथा सरकार को इसका प्रतिवेदन कब तक प्राप्त हो जाने की सम्भावना है;

(ग) क्या यह भी सच है कि उक्त समिति का प्रतिवेदन प्रस्तुत होने से पहले ही भारतीय खाद्य निगम द्वारा 1 अगस्त, 1994 से गेहूं के केन्द्रीय निर्गम मूल्यों में वृद्धि की गई है;

(घ) यदि हां, तो मूल्यों में कितनी वृद्धि की गई है और प्रतिवेदन से पूर्व मूल्य वृद्धि करने के क्या कारण हैं;

(ङ) क्या यह भी सच है कि भारतीय खाद्य निगम द्वारा गेहूं की आर्थिक लागत में भी गत वर्षों की तुलना में निरन्तर वृद्धि की जा रही है; और

(च) यदि हां, तो 1992-93 के वर्षों में गेहूं की आर्थिक लागत पृथक-पृथक कितनी थी तथा वर्ष 1994-95 में इसमें कितनी वृद्धि होने का अनुमान है?

खाद्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कल्प नाथ राय): (क) से (घ): गेहूं के न्यूनतम समर्थन मूल्य में हुई वृद्धि और भारतीय खाद्य निगम की हैंडलिंग लागत को आंशिक रूप से खपाने के लिए सरकार द्वारा समय-समय पर गेहूं के केन्द्रीय निर्गम मूल्य (भारतीय खाद्य निगम के गोदामों से) में वृद्धि की जाती है। गेहूं का वर्तमान केन्द्रीय निर्गम मूल्य 402 रुपए प्रति क्विंटल है, जो 1.2.1994 से प्रभावी है।